एक्सचेंज खोलने के लिए राजस्थान सरकार से कोई प्रस्ताव मिला है ;

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गई है ; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्री (श्री आर० वेंकटरामण) : (क) प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 के विनियमनकारी उपबन्धों के अन्तर्गत देश के विभिन्न भागों में नए स्टाक एक्सचेंज की स्थापना करने के प्रश्न पर सरकार मुक्त दृष्टिकोण से विचार करती है। विभिन्न केन्द्रों मे प्राप्त होने वाले प्रस्तावों पर उनके गुणावगुणों के आधार विचार किया जाता है।

(ख) से (घ). जयपुर में स्टाक एक्सचेंज की स्थापना करने के लिए राजस्थान सरकार से कोई भी प्रस्ताव अभी तक केन्द्रीय सरकार को नहीं मिला है। तथापि राजस्थान वाणिज्य एवं उद्योग मण्डल, जयपुर की तरफ से इस आशय का एक प्रस्ताव अवश्य प्राप्त हुआ है। राजस्थान में स्थित पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों की संख्या राजस्थान में शेयरधारी लोगों की अनुमानित संख्या, ऐसे व्यक्तियों के नाम तथा उनकी योग्यताएं जो प्रस्तावित स्टाक एक्सचेंज के सदस्य बन सकते हैं तथा इस समय जयपुर में होने वाले सिक्यूरिटियों के लेनदेन के अनुमानित परिमाण आदि के सम्बन्ध में, राजस्थान वाणिज्यक एवं उद्योग मंडल जयपुर से विस्तृत जानकारी मांगी गई है ताकि सरकार इस मामले में आगे कार्यवाही कर सके। अभी तक उक्त मण्डल से इस सम्बन्ध में कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।

Permission to Tamil Nadu to Import Raw Silk

2909. SHRI N. SOUNDARAJAN:

SHRI C. CHINNASWAMY:

Will the Minister of COMMERCE be pleased to state:

(a) whether Government of Tamil Nadu has asked the permission of the Centre to import raw silk to meet the shortage faced by the looms in Tamil Nadu;

(b) if so, the details thereof; and

(c) when the permission will be granted?

THE MINISTER OF COMMERCE AND STEEL AND MINES (SHRI PRANAB MUKHERJEE): (a) to (c). No formal request has been received from the Government of Tamil Nadu for permission of the Centre to import raw silk to meet the shortage faced by the looms in Tamil Nadu. However, Director of Handlooms, Tamil Nadu, has requested Development Commissioner for Handlooms to move Government of India to grant necessary permission to the Tamil Nadu State Handloom Weavers Apex Cooperative Society (COOPTEX) to import at least 10,000 Kgs. of raw silk under Open General Licence scheme. Under the existing policy, there is no provision for import of raw silk for actual users except through the Central Silk Board which also is not at present authorised to utilise this provision in view of the review of the raw silk price stabilisation scheme. Raw Silk could be imported by the exporters only against their export performance according to a formula prescribed under the replenishment scheme. Hence the question of giving permission to COOPTEX to import raw silk does not arise.